राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 62 | जौनपुर बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

ट्रंप ने मुनीर को कहा पसंदीदा फील्ड मार्शल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की प्रशंसा करने पर सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रंप को खुश करने की हताश कोशिशों के बावजूद, अमेरिकी नेता भारत को कैसा संकेत दे रहे हैं। विपक्षी दल ने ट्रंप द्वारा मुनीर की प्रशंसा और दोनों के बीच पिछली मुलाकातों का हवाला देते हुए पूछा कि ट्रंप और मोदी के बीच यह कैसी दोस्ती है। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहते हैं और सच कहें तो अमेरिकी नेता भी मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते रहते हैं। रमेश ने एक्स पर कहा कि लेकिन यह कैसी दोस्ती है? राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 जून, 2025 को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए एक अभूतपूर्व लंच की मेजबानी की। ये वही फील्ड मार्शल थे जिनकी भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से जहरीली टिप्पणियों ने 22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने 1 अक्टूबर, 2025 को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल से दूसरी बार मुलाकात की, जब फील्ड मार्शल ने राष्ट्रपति ट्रम्प को दुर्लभ मृदा तत्वों से भरा एक बॉक्स भेंट किया।

अदालतों के प्रति जनता में बढ़ती निराशा चिंता की बात है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को हमेशा अंतिम आशा का केंद्र माना गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में यह संस्था न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी दायित्व निभाती है। परंतु हाल के वर्षों में आम जनता के बीच एक गहरी निराशा उभरती दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसका पहला कारण है न्याय में देरी। वर्षों तक लंबित मामलों का बोझ इतना बढ़ गया है कि गरीब और आम नागरिक को न्याय पाने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं। "न्याय में देरी, न्याय से इंकार है", यह कहावत आज न्यायपालिका की सच्चाई बनती जा रही है। दूसरा कारण है सार्वजनिक हित के मुद्दों पर अनिश्चित रुख। तीसरा कारण है स्वतः संज्ञान लेने में चयनित रवैया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर स्वतः संज्ञान लेकर मामलों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कई संवेदनशील और व्यापक सामाजिक समस्याओं पर इसकी सक्रियता नदारद रहती है। उदाहरण के लिए, हर साल लगभग पाँच लाख बहन–बेटियों के गायब होने, धर्मांतरण या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन जैसी समस्याओं पर अदालत की। ओर से कोई ठोस स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता। जब आम नागरिक के लिए जीवन और सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे अदालत के ध्यान से बाहर रह जाते हैं, तो न्यायपालिका के रुख पर निराशा होना स्वाभाविक है। चौथा पहलू है।

भूमि उपयोग के आधार पर शुल्क दरों में अंतर रखा जाए : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के नगरों के तीव्र गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए अब एक व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति की आवश्यकता है। यह नीति केवल भवनों के पुनर्निर्माण तक सीमित न रहकर शहरों के समग्र पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे नगर केवल इमारतों का समूह नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक संरचनाएं हैं। इनके पुनर्जीवन के लिए ऐसी नीति आवश्यक है, जो आधुनिकता, परंपरा और मानवता तीनों का संतुलित समन्वय करे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आवास विभाग की बैठक में कहा, नई नीति का उद्देश्य पुराने, जर्जर और अनुपयोगी क्षेत्रों को आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकसित करना है। नीति में ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिनसे निवास योग्य, सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण

सुनिश्चित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नीति में भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश को प्रोत्साहन, पारदर्शी पुनर्वास व्यवस्था और प्रभावित परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। हर परियोजना में जनहित सर्वोपरि की भावना हो तथा किसी की संपत्ति या जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए न्यायसंगत और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। सीएम योगी ने कहा, नई नीति में राज्य स्तरीय पुनर्विकास प्राधिकरण, परियोजनाओं की सिंगल विंडो अप्रूवल प्रणाली व पीपीपी मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। निवेशकों को स्पष्ट दिशा–निर्देश, प्रोत्साहन और सुरक्षा दी जाए, ताकि निजी क्षेत्र पुनर्विकास में सक्रिय भागीदारी कर सके। साथ ही हर परियोजना में हरित भवन मानक, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रावधान अनिवार्य किए जाएं। नगरों की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुराने बाजारों, सरकारी आवास परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों और अनधिकृत बस्तियों के लिए क्षेत्रवार अलग रणनीति तैयार की जाए। नीति में सेवानिवृत्त सरकारी आवासों, पुरानी हाउसिंग सोसाइटियों व अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

कितना भी बड़ा हो पद, न्याय होकर रहेगा – चिराग पासवान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, जिनकी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी माँगें पूरी की जाएँगी और बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत आईपीएस अधिकारी के परिवार से मिलने के बाद पासवान ने कहा कि यह दुखद घटना मौजूदा सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि कैसे 21वीं सदी में भी लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर सताया जाता है। युवा नेता ने कहा कि आज मैं चिराग पासवान के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में परिवार से मिलने आया हूँ। मैं अपनी सरकार का आश्वासन लेकर आया हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि परिवार की हर माँग पूरी की जाएगी और बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जाएगी... अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो कोई भी दलित परिवार मुख्यधारा में शामिल होने के बारे में नहीं सोचेगा।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा सार्वजनिक जीवन में पूरन कुमार की सेवाओं और ईमानदारी की सराहना की। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जो शोक संतप्त परिवार के साथ पार्टी की एकजुटता को दर्शाता है, ।

उनके कण–कण में था हिमाचल' : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को शिमला में रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।सीबीआई अदालत का फैसला इस दौरान उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, पार्टी महासचिव सचिन पायलट, पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रियंका

गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ऐसे शख्स थे, जिनके कण–कण में हिमाचल था। उन्होंने एक चाय की दुकान के किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह का व्यक्तित्व इतना मिलनसार था कि जनता को यह महसूस नहीं होता था कि वह मुख्यमंत्री हैं, जनता उन्हें अपना मानती थी। लगातार पराजय से हताश होकर कर रही ओछी राजनीति कांग्रेस महासचिव ने कहा कि नेताओं का जनता से ऐसा जुड़ाव ही कांग्रेस की परंपरा है, जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री सुक्खू भी इसी परंपरा को निभाते हैं, वे सरलता से जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, उनके बीच रहते हैं। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर प्रदेश की अनदेखी के पुख्ता आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई भयंकर तबाही के बावजूद कांग्रेस सरकार होने के कारण मोदी सरकार ने आवश्यक मदद नहीं दी।

गांधी के शांति दर्शन से विश्व का होगा मार्गदर्शन - राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि शांति भारत के अहिंसा और सत्य के दर्शन में गहराई से समाहित है, जिसका प्रचार महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना केवल एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए, जिसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है, सिंह ने संघर्षों और हिंसा पर मानवता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने कहा कि शांति हमारे अहिंसा और सत्य के दर्शन में गहराई से निहित है। महात्मा गांधी के लिए,

शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि न्याय, सद्भाव और नैतिक शक्ति की एक सकारात्मक स्थिति थी। हम सभी जानते हैं कि शांति स्थापना एक सैन्य मिशन से कहीं बढ़कर है। यह एक साझा जिम्मेदारी है। यह हमें याद दिलाती है कि संघर्षों और हिंसा से ऊपर, मानवता है जिसे कायम रखने की आवश्यकता है। इस मिशन के लिए, जब युद्ध से तबाह लोग ब्लू हेल्मेट्स को देखते हैं, तो यह उन्हें याद दिलाता है कि दुनिया ने उन्हें त्यागा नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 29,000 भारतीय कर्मियों ने कांगो और कोरिया से लेकर दक्षिण सूडान और लेबनान तक, 50 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी सेवाएँ दी हैं। सिंह ने आगे कहा कि पिछले दशकों में, लगभग 2,90,000 भारतीय कर्मियों ने 50 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी सेवाएँ दी हैं और अपने पेशेवर कौशल, साहस और करुणा के लिए वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। कांगो और कोरिया से लेकर दक्षिण सूडान और लेबनान तक, हमारे सैनिक, पुलिस और चिकित्सा पेशेवर कमजोर लोगों की रक्षा और समाज के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का योगदान बलिदान से रहित नहीं है, क्योंकि देश के 180 से ज़्यादा शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने प्राणों की आहुति दी है ।

आतंकवाद के खिलाफ एनएसजी का नया युग - अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पिछले चार दशकों से आतंकवाद के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के प्रयासों की सराहना की। एनएसजी की कार्रवाई के प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए, शाह ने कहा कि इससे देश को संतुष्टि मिलती है कि उसकी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सुरक्षित हाथों में है। शाह ने हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वत्र, सर्वोत्तम, सुरक्षा इन तीन सिद्धांतों के साथ और समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपनी पहचान बनाकर, एनएसजी ने चार दशकों तक इस देश में संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ी है। शाह ने कहा कि हम सभी ने अभी–अभी देखा है कि इस प्रदर्शन को देखने के बाद, देश का प्रत्येक नागरिक अपने दिल और दिमाग में इस संतुष्टि के साथ जा रहा है कि हम, हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है। शाह ने कहा कि आज जिस विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (एसओटीसी) का उद्घाटन किया गया, वह न केवल एनएसजी के लिए, बल्कि राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने के लिए भी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं सभी राज्य पुलिस बलों को बताना चाहता हूँ कि आज जिस विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वह केवल एनएसजी के लिए ही नहीं, बल्कि आप सभी को प्रशिक्षित करने के लिए भी है। हम एनएसजी की भूमिका में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। एनएसजी का नया केंद्र अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही, एनएसजी के सभी छह केंद्र, जिन्हें एसएसजी के नाम से जाना जाता है, किसी भी आतंकी हमले को कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से लेकर, हमने आतंकवादियों के प्रमुख ठिकानों पर हमला किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ आतंकवादियों और उनके एजेंडे को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। शाह ने बताया कि 141 करोड़ रुपये की लागत से एसओटीसी का उद्घाटन किया गया है और यह कमांडो को आतंकवाद से निपटने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लुधियाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे

लुधियाना, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पंजाब के लुधियाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान श्री चौहान कई कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे तथा अग्रणी कृषि संस्थानों का दौरा करने के साथ किसानों और स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही, पंजाब के बाढ़ प्रभावित निवासियों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मौके पर ही केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह दिल्ली से प्रस्थान कर चंडीगढ़ होते हुए लुधियाना पहुंचेंगे। उनके लुधियाना प्रवास की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में नवनिर्मित

प्रशासनिक भवन के उद्घाटन से होगी। इसी संस्थान परिसर में वे ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण विकास पहलों तथा पंजाब क्षेत्र के लिए योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री चौहान ग्राम नूरपुर बेट, लुधियाना में किसानों के साथ चौपाल में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर धान की कटाई के लिए एसएसएमएस फिटेड कंबाइन हार्वेस्टर और गेहूं की बुआई के लिए हैप्पी स्मार्ट सीडर मशीन का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। तत्पश्चात, चौहान डोराहा में समन्यु हनी मधुमक्खी पालन केंद्र का अवलोकन करेंगे, जहां वे क्षेत्र के किसानों से संवाद कर इस व्यवसाय के नए मॉडल और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय की संबंधित योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे।

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को दिया सबसे जल्दी और ज्यादा मुआवजा – केजरीवाल

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिशन चढ़दीकला के तहत राहत राशि वितरित की। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की तारीफ की। सीबीआई अदालत का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने एक और ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित परिवारों और किसानों को आज तक का सबसे जल्दी मुआवजा दिया गया है। सिर्फ 30 दिन के अंदर ही 20 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा किसानों के खाते में आना शुरू हो गया है। ये सिर्फ

सरकार ही कर सकती थी। हमने अच्छी नीयत वाली एक ईमानदार इसे कर दिखाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि पंजाब के किसानों को सबसे कम समय में सबसे अधिक मुआवजा दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को एक महीने के अंदर ही 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से वादा किया था कि वे उन्हें देश का सबसे अधिक मुआवजा सबसे कम समय में देंगे। आज उन्होंने किसानों से किया अपना वादा पूरा किया। से हताश होकर कर रही ओछी राजनीति सोमवार को सीएम भगवंत मान ने कहा कि 11 सितंबर को प्रेस वार्ता में वादा किया था कि 45 दिन में गिरदावरी करके मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन आज 32 दिन ही हुए हैं कि हम मुआवजा राशि के चेक सौंप रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों में भी बाढ़ आई है, लेकिन तब किसानों को 25 से 37 रुपए के चेक दिए गए, वह भी 1.5 साल बाद। खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले नेता किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक करते थे। सीएम भगवंत ने कहा कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं। हमारी खुद की जमीन पहले डूबती रही है। हमारी भी गिरदावरी होती थी।

गुजरात में 14-15 अक्टूबर को 'रबी कृषि महोत्सव-2025' का आयोजन

गांधीनगर, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी जनसेवा यात्रा के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समग्र गुजरात में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान विभिन्न थीमों पर आधारित 'विकास सप्ताह' मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 14 अक्टूबर को 'कृषि विकास दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को एनएसई पर सूचीबद्ध कृषि विकास दिवस के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से 14 और 15 अक्टूबर को 'रबी कृषि महोत्सव–2025' का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को मौजूदा समय के अनुरूप कृषि पद्धतियों, टेक्नोलॉजी और नवीन दृष्टिकोण से परिचित कराना है। कृषि क्षेत्र और राज्य के किसानों को समर्पित 'कृषि विकास दिवस' के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री राघवजी पटेल पंचमहाल–गोधरा के छबनपुर गांव में राज्यव्यापी 'रबी कृषि महोत्सव–2025' का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने श्रबी कृषि महोत्सव–2025

के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि विकास सप्ताह के तहत 14 और 15 अक्टूबर को राज्य में कुल 261 स्थानों पर जिला और तहसील स्तरीय रबी कृषि महोत्सव–2025 का आयोजन किया जाएगा। गुजरात सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों सहित विभिन्न पदाधिकारी और उच्च अधिकारी जिला और तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस दो दिवसीय रबी कृषि महोत्सव में गुजरात के लगभग 3 लाख से अधिक किसान हिस्सा लेंगे।कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं रू रवि कुमार त्रिपाठी उन्होंने कहा कि रबी कृषि महोत्सव के दौरान गुजरात सरकार राज्य के प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों को विशेष रूप से सम्मानित करेगी। इसके अलावा, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 500 करोड़ रुपए की सहायता के मंजूरी पत्र और सहायता आदेश का भी वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों को उनके क्षेत्रों में रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के अलावा प्राकृतिक खेती और बागवानी फसलों में नवीनतम टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों पर भी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही, प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के प्रतिनिधियों द्वारा भी विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए जाएंगे।

संपादकीय

तालिबान का ऐसा रुतबा!

मुत्ताकी ऐसी सरकार के विदेश मंत्री हैं, जिसे आज भी ज्यादातर देशों की मान्यता हासिल नहीं है। वे अपने देश के कायदे यहां लागू करना चाहें और कामयाब हो जाएं, तो उस पर आक्रोश ही जताया जा सकता है!

यह अपने वर्तमान और भारत की विदेश नीति पर एक प्रतिकूल टिप्पणी है। संभवतरू अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने इच्छा जताई कि नई दिल्ली में उनकी प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाया जाए और भारत सरकार ने उसे पूरा किया! मुत्ताकी ऐसी सरकार के विदेश मंत्री हैं, जिसे आज भी ज्यादातर देशों की मान्यता हासिल नहीं है। वे अपने देश के श्तालिबानीय कायदे नई दिल्ली में लागू करना चाहें और उसमें कामयाब हो जाएं, तो उस पर आक्रोश जताने के अलावा और क्या किया जा सकता है! फिर देवबंद यात्रा के दौरान मुत्ताकी को देखने के लिए जिस तरह हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा, वह भी कोई कम अफसोसनाक नजारा नहीं था। वहां आए लोग टीवी रिपोर्टरों से कहते सुने गए कि मुत्ताकी वह हस्ती हैं, जिनके संगठन ने दुनिया की दो महाशक्तियों (सोवियत संघ और अमेरिका) को पराजित कर दिया। उनके इस मॉडल की कभी यहां भी जरूरत पड़ सकती है (अगर किसी विदेश ताकत ने हम पर हमला किया तो)। उध ार नई दिल्ली की प्रेस कांफ्रेंस में मुत्ताकी भारत को यह सलाह दे गए कि वह अटारी– वाघा बॉर्डर को राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक नजरिए से देखे और उसे खोल दे, क्योंकि भारत– अफगानिस्तान के बीच व्यापार का वह सबसे छोटा रास्ता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को मिल कर चाबहार बंदरगाह के विकास के रास्ते की रुकावटें दूर करनी चाहिए और इसके लिए दोनों को मिल कर अमेरिका और ईरान से बात करनी चाहिए। मौजूदा भारतीय विदेश नीति के नजरिए से ये बातें कहां फिट बैठती हैं, इस सहज समझा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुत्ताकी की यात्रा से ठीक पहले भारत ने मॉस्को कंसल्टेशन ग्रुप के उस साझा बयान पर दस्तखत किया, जिसमें बागराम एयरपोर्ट को फिर से अमेरिकी कब्जे में लेने के डॉनल्ड ट्रंप के इरादे को अस्वीकार किया गया है। तालिबान सरकार पर भारत इतना मेहरबान क्यों है, इसे समझना आसान नहीं है। बेशक अफगानिस्तान में भारत के रणनीति हित हैं, लेकिन क्या उन्हें उन्हें साध ाने की शर्त तालिबान की इस हद तक मिजाजपुर्सी है?

कहीं दिल्ली पेयजल की प्यासी न हो जाए!

विनीत नारायण

गौरतलब है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी पानी के अभाव के कारण मात्र 15 सालों में ही उजड़ गई थी।ज् दिल्ली का संकट केवल एक चेतावनी है। आने वाले वर्षों में संकट और बढ़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर श्जल–विहीनय क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब समय है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाएँ। इस वर्ष देश भर में हुई भारी बारिश और जल प्रलय के बावजूद भारत के शहरी क्षेत्रों में जल संकट है। पेयजल संकट आशंका नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगर, जो आर्थिक प्रगति और आधुनिक जीवनशैली के प्रतीक हैं, अब जल प्रबंधन की विफलता के गंभीर परिणाम झेल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में तीन बड़े मॉल और आसपास की सप्लाई के पूरी तरह ठप हो जाने से यह संकट फिर सुर्खियों में आया। इन प्रतिष्ठानों को बंद करने की नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि टैंकरों से इनकी जल आपूर्ति रुक गई, जबकि भूजल दोहन (ग्राउंड वॉटर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह स्थिति केवल अस्थायी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नैतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबों रुपया जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा है तो आखिर क्यों??

दिल्ली महानगर की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। इससे जल आपूर्ति की व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि उपलब्धता मुश्किल से 850 मिलियन गैलन तक पहुँच पाती है। वसंत कुंज जैसे पॉश इलाकों में भी पिछले कुछ वर्षों से पानी की टंकियों और निजी टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी है। परंतु इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह हो गई क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक कारणों से टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सबसे बड़ा असर व्यापारिक केंद्रों जैसे मॉल्स, रेस्तरां और दुकानों पर पड़ा है। इन मॉल्स में हजारों कर्मचारी काम करते हैं और प्रतिदिन लाखों ग्राहक आते हैंय बिना पानी के ऐसी व्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। शौचालय, सफाई, भोजनालय, अग्निशमन प्रणाली, सब कुछ जल आपूर्ति पर निर्भर हैं। जब टैंकरों की आपूर्ति रुकी, तो केवल व्यापार ही नहीं, आसपास के आवासीय समाज भी संकट में पड़ गए। दिल्ली सरकार ने कुछ वर्ष पहले भूजल दोहन पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। उद्देश्य यह था कि गिरते जलस्तर को रोका जाए। यह पहल पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक था, क्योंकि लगातार बढ़ते दोहन ने दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल को 300 फीट से भी अधिक नीचे पहुँचा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित की गई? जब सरकार ने ग्राउंड वॉटर बोरिंग को गैरकानूनी घोषित किया, तब उसके समानांतर रूप में मजबूत टैंकर नेटवर्क, पुनर्चक्रण संयंत्र और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश, नीतियाँ बनीं पर उनका कार्यान्वयन अधूरा रह गया। परिणामस्वरूप, लोग न तो कानूनी तरीके से पानी निकाल सकते हैं, न सरकारी वितरण पर भरोसा कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि जाड़ों में यह हाल है तो गर्मियों में क्या होगा? दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पानी की आपूर्ति से जुड़ा टैंकर कारोबार वर्षों से विवादों में रहा है। कई जगह यह सार्वजनिक सेवा से अधिक निजी व्यवसाय बन चुका है। अधिकारियों और टैंकर ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के आरोप नए नहीं हैं। दिल्ली में जल आपूर्ति में आई यह हालिया बाधा भी ऐसे ही भ्रष्टाचार की परतें उजागर करती प्रतीत होती है। त्योहारों के मौसम में जब पानी की मांग बढ़ जाती है, घरों में सजावट, साफ–सफाई और उत्सव आयोजन अधिक होते हैं। ऐसे समय पर टैंकरों की आवाजाही पर प्रतिबंध या श्तकनीकी समस्याय का बहाना बना देना संदेह उत्पन्न करता है। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ जल एजेंसियों ने टैंकरों की उपलब्धता को कृत्रिम रूप से सीमित कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश की है। इससे न केवल आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा, बल्कि मॉल्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की स्थिति आ गई। अगर यह सही हैं,।

शहबाज शरीफ ने चापलूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान के मस्तक पर चमचे का ताज सजा दिया है

नीरज

शर्म–अल–शेख में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन का मंच सिर्फ पश्चिम एशिया की राजनीति का नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के भविष्य के संकेतों का भी साक्षी बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब

सार्वजनिक रूप से कहा कि "भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से साथ रहेंगेश्श और साथ ही भारत को "महान देश" बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की, तो यह केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था। यह बयान दरअसल उस रणनीतिक संदेश का प्रतीक है, जिसके जरिए ट्रंप एक साथ दोनों एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना चाहते हैंकृ लेकिन प्राथमिकता के पलड़े भारत की ओर झुके दिखते हैं। ट्रंप के इस वक्तव्य के पीछे दो परतें साफ दिखती हैं। पहली यह है कि वह यह जताना चाहते हैं कि उनकी मध्यस्थता के बिना भारत–पाक युद्ध छिड़ जाता, जो अमेरिकी षविश्व उद्धारकष की छवि को पुनः स्थापित करने की कोशिश है। दूसरी, मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया "उल जैसा संबोधन न सिर्फ व्यक्तिगत निकटता दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति अब पाकिस्तान की "रणनीतिक उपयोगिता" से कहीं आगे निकल चुकी है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह वह क्षण था जब कूटनीति की मेज पर "संवाद के साथ संप्रभुता" का भारतीय मॉडल विजयी होता दिखा। भारत ने न तो अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार किया, न ही पाकिस्तान की शांति–अभिनय की भाषा में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे प्रसंग को संयमित शब्दों में संभालते हुए ट्रंप की भूमिका की सराहना तो की, पर स्पष्ट किया कि भारत शांति के लिए "प्रत्यक्ष बातचीत" में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के प्रयासों की "ईमानदारी" को रेखांकित करते हुए गाजा में बंधकों की रिहाई पर मानवता की जीत पर जोर दिया, न कि किसी नेता की। इसके बरअक्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रवैया चौंकाने वाला और कुछ हद तक लज्जाजनक रहा। ट्रंप की प्रशंसा में उन्होंने जिस तरह चापलूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वह पाकिस्तान की कूटनीतिक निर्भरता का प्रतीक बन गया। "मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करता हूँ," से लेकर "अगर यह सज्जन न होते तो भारत–पाकिस्तान युद्ध में कोई जीवित न बचता" तक, हर वाक्य आत्मसमर्पण जैसा लगा। यह सिर्फ अमेरिकी कृपा पाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपने घरेलू असंतोष और सैन्य दबावों के बीच शरीफ द्वारा सुरक्षा–राजनीति की लगाम वॉशिंगटन के हाथों में सौंपने जैसा कृत्य था। यह वही पाकिस्तान है जिसने वर्षों तक अमेरिका से ष्समानताष की मांग की, पर अब एक नेता के व्यक्तिगत "धन्यवाद" में अपनी संप्रभुता का स्वर खो बैठा। शहबाज शरीफ का यह रवैया दो बातों को उजागर करता है। पहला यह कि पाकिस्तान की विदेश नीति आज आत्मनिर्भरता से कोसों दूर है और दूसरा यह कि शहबाज अपनी नाकामी को अमेरिकी प्रशंसा से ढंकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, ट्रंप की मुस्कराहट वाली तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। ट्रंप ने जिस सहजता से कहा ", वह एक राजनीतिक व्यंग्य था। यह संकेत था कि अमेरिका अब दक्षिण एशिया में "मध्यस्थ" नहीं बल्कि "निर्देशक" की भूमिका निभाना चाहता है और शहबाज शरीफ ने उसी वाक्य को अपने "कृतज्ञता के ग्रंथ" में बदल डाला। हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप की "शांति की राजनीति" में भारत की भूमिका गरिमा के साथ सीमित रही। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह का सम्मेलन में उपस्थित होना और भारत का आधिकारिक वक्तव्य, दोनों ने यह संदेश दिया कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर "दूसरों के सहारे" नहीं बल्कि "अपने सिद्धांतों" पर खड़ा रहेगा। इस पूरी घटना का सार यही है कि जहाँ ट्रंप अपनी चुनावी छवि के लिए वैश्विक शांति–स्थापक का वस्त्र पहन रहे हैं, वहीं शहबाज शरीफ अपने कूटनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए उस वस्त्र के किनारे झाड़ रहे हैं। मोदी की शांत–नपी–तुली प्रतिक्रिया और शहबाज शरीफ की अतिशय प्रशंसा का यह विरोधाभास न केवल तीन नेताओं के व्यक्तित्व का अंतर बताता है, बल्कि दक्षिण एशिया के शक्ति–संतुलन का भी प्रतीक है। शर्म–अल–शेख का यह दृश्य इतिहास में शायद "गाजा शांति सम्मेलन" के नाम से दर्ज होगा, पर भारत और पाकिस्तान के लिए यह एक और संकेत छोड़ गया कि जो नेतृत्व अपने राष्ट्रीय सम्मान को दूसरों की तारीफों में खो देता है, वह शांति नहीं, पराधीनता का मार्ग चुनता है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेताओं की भाषा और बर्ताव ही यह तय करते हैं कि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व किस गरिमा से कर रहे हैं। बहरहाल, वैसे तो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच किसी तरह की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन दो पड़ोसी राष्ट्रों के नेतृत्व के बीच का अंतर इस मंच पर साफ दिखाई दिया। मोदी ने भारत के स्वाभिमान को दृढ़ता से बरकरार रखा और ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा की, ना कि मोदी ने ट्रंप की प्रशंसा की। इसके उलट, शहबाज शरीफ ने अपने देश के स्वाभिमान की चिंता किए बिना सार्वजनिक मंच से ट्रंप की खुलेआम चापलूसी की। यह दृश्य दक्षिण एशिया की बदलती राजनीतिक मानसिकता और नेतृत्व की गुणवत्ता पर गहरी टिप्पणी छोड़ गयाकृ जहाँ भारत का नेतृत्व आत्मगौरव और संतुलन का प्रतीक बनकर उभरा, वहीं पाकिस्तान का नेतृत्व आत्मविश्वासहीनता और निर्भरता की छवि में सिमट गया।

सोच के स्तर पर बदल रही बिहारी राजनीति

उमेश

बिहार की राजनीति जाति और ध र्म से कभी अलग नहीं रही। आजादी के फौरन बाद के चुनावों में जाति का असर कम रहा, क्योंकि तब स्वाध ीनता संग्राम के दौरान अर्जित नैतिक मूल्यों की आभा और स्मृति बनी हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में यह लगातार कम होता चला गया। जाति और धर्म की राजनीति तब भी होती थी, लेकिन उस पर स्वाधीन भारत को बनाने के लिए सर्वसमावेशी सोच का आवरण बना रहा। लेकिन मंडल आयोग की छाया में उभरी राजनीति के बाद जाति और धर्म का खुला–खेल शुरू हो गया। जातीय गोलबंदी खुलेआम होने लगी। बिहार के वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य ने जब लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया था, तब शासन सौंपने वाले हाथों की योग्यता उनकी न्याय प्रियता, उनकी प्रशासनिक कुशलता और निष्पक्षता थी। इसे बिडंबना ही कहेंगे कि जिस बिहार की धरती ने छठी सदी ईसापूर्व यानी करीब ढाई हजार साल पहले शासन के बेहतरीन मॉडल को अपनाया, उसी धरती पर वैधानिकता के आधार पर लागू लोकतंत्र ने जाति, धर्म और क्षेत्रवाद को खुद में समाहित कर लिया। लेकिन इस बार के चुनावों में लोकतंत्र का जातीय और धार्मिक मॉडल को किंचित चोट पहुंचती दिख रही है। बिहार गर्व करते नहीं अघाता कि उसकी धरती पर लोकतंत्र का जन्म हुआ। इसी लोकतंत्र की छांव में बिहार और प्रकारांतर से देश को आगे बढ़ाने का सपना जयप्रकाश नारायण ने देखा था। जब भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल की काली छाया पड़ी तो जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण की अगुआई में बिहार की ही धरती ने बिगुल फूंक दिया। इस बिगुल ध्वनि को देश ने सुना और जेपी के पीछे हो लिया। जिसकी परिणति आपातकाल के काले दिनों के अंत और बाद में आपातकाल थोपने वाले हाथों यानी इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक हार के रूप में देश और दुनिया ने देखा। जेपी की राजनीति में जाति और धर्म का आध ार नहीं था। जेपी के पीछे पहले बिहार और बाद में तकरीबन उत्तर भारत जब चल पड़ा, तब देश और ध र्म की बातें पीछे छूट गई थीं। तब देश को बनाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर धर्म, हर जाति और हर समूह ने अपने जातीय, ध ार्मिक और स्थानीय हितों को किनारे रख दिया और देश के लिए आगे चल पड़े थे। दुर्भाग्यवश उसी दौर में उभरे नेताओं ने जाति का सबसे बड़ा खेल खेला। बिहार की जातीय राजनीति को बढ़ावा देने में उसी दौर में उभरे नेताओं ने सबसे ज्यादा दिया। आज की बिहारी राजनीति के चमकते सितारे लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, नंद किशोर यादव, आदि उसी दौर में उभरे चेहरे हैं। बाद के दौर में बिहार के चुनाव की चर्चा जाति और धर्म की बुनियाद को आधार बनाए असंभव मानी जाने लगी। वैसे यह रोग तकरीबन हर राज्य की राजनीति को लगा है। कहीं इसकी तासीर कम दिखती है तो कहीं कम, लेकिन यह हर जगह है। लेकिन बिहार के इस चुनाव में प्रशांत किशोर के जरिए कम से कम जातीय गोलबंदी की बात को लगाम पहुंची है। प्रशांत किशोर का चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, जितना भी उपहास उड़ाने की कोशिश करे, उन्होंने बिहारी राजनीति को नया चेहरा जरूर दिया है। प्रशांत ब्राह्मण परिवार के बेटे हैं। उनकी राजनीतिक आभा से परेशान बिहार का सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष की ओर से उन्हें ब्राह्मण बताने की कोशिश खूब हुई। लेकिन यह कार्ड चल नहीं पाया। दरअसल मंडलवाद की राजनीति के उभार के बाद सवर्णवाद की बात करने की हिम्मत भी दिखाना मुश्किल है। सवर्ण तबके की जातियां और उनके नेता अपनी जाति की बात कर लें तो उन पर जातिवादी ठप्पा लगाकर ट्रोल किया जाता रहा है। वैसे आज का जो विमर्श है, उसमें सवर्ण तबके की अपनी जाति की बात करना जातिवादी होना है और पिछड़े एवं दलित जातियों की बात करना उनका सशक्तीकरण एवं प्रगतिवाद का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। जेपी के बाद बिहार की तकरीबन हर जातियों में जिस राजनेता की व्यापक स्वीकृति रही, वे कर्पूरी ठाकुर हैं। दिलचस्प यह है कि आज के बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता हैं, सब कर्पूरी ठाकुर का नाम ही जपते हैं। यह बात और है कि कर्पूरी ठाकुर जैसी सादगी, उनके जैसी सर्वसमावेशी राजनीति की राह उनके चेलों ने नहीं अपनाई। बिहार की राजनीति के दोनों दिग्गज चेहरे जेपी और कर्पूरी की राजनीति में संकीर्णता का आधार नहीं नहीं था। वे जातीय गोलबंदी की बजाय सर्वसमावेशी राजनीति की बात करते थे। आज की राजनीति और सामाजिक संतुलन के लिए आरक्षण व्यवस्था की जरूरत को कर्पूरी ठाकुर स्वीकार करते थे, लेकिन उनकी आरक्षण व्यवस्था में किसी खास वर्ग को लक्षित करने और उस पर निशाना साधने का भाव नहीं था। उन्होंने आरक्षण का जो फॉर्मूला दिया था, उसमें पिछड़ा वर्ग को बारह प्रतिशत, अति पिछड़े वर्ग को आठ प्रतिशत, महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत और गरीब सवर्णों के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान किया था। चाहे लोहिया की आरक्षण को लेकर सोच रही हो या फिर कर्पूरी का मॉडल, दोनों का मकसत सामाजिक विकास की दौड़ में पीछे रहे वर्ग को आगे रहे वर्गों के समकक्ष खड़ा करना और इस तरह बराबरी का बोध लाना था। यही वजह रही कि इन नेताओं के पीछे समाज का बड़ा हिस्सा खड़ा होता था, जहां जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाया करती थीं। इसका यह मतलब नहीं था कि तब जातीय गोलबंदी खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह जरूर है कि ऐसा करने वाली ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलता था। लेकिन जेपी और कर्पूरी के बाद स्थितियां बदल गईं। बिहार के मौजूदा चुनावों में प्रशांत किशोर के अभ्युदय ने जातीय गोलबंदी की इस रूढ़ि को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रशांत किशोर ने अपना दल बनाने के बाद एक गलती जरूर की। उन्होंने तब जरूर कहा था कि मुस्लिम समुदाय को तरजीह देंगे। ऐसा करके वे एक तरह से धार्मिक गोलबंदी की पारंपरिक अवधारणा को जरूर शह दे

रहे थे। लेकिन शायद बाद में उन्हें इस गलती का अहसास हुआ और उन्होंने इस सोच का मुजाहिरा फिर नहीं किया। प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में उभार के बाद मुद्दों की बात हो रही है। महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने का मौजूदा नीतीश सरकार का फैसला हो या फिर तेजस्वी द्वारा हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का वादा, प्रशांत किशोर की राजनीतिक शैली का दबाव माना जा सकता है। प्रशांत किशोर बार–बार बिहार की बदहाली का सवाल उठाते हैंवैश्विक स्तर पर मजदूर सप्लाई करने वाले राज्य के रूप में बिहार की स्थापित छवि पर सवाल उठाते हैं, बिहार को नई राह पर लेकर चलने की बात करते हैं, जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाते हें तो बिहार के पढ़े–लिखे युवाओं और बिहार की मौजूदा छवि से परेशान लोगों को उनकी बात अपील करती है। पिछली सदी के साठ के दशक तक प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देश का पांचवां बड़ा राज्य रहे बिहार की बदहाली का सवाल जब वे उठाते हैं तो बिहार का हित चाहने वाले लोगों को वह बात अपील करती है। यही वजह है कि उनके साथ हर वर्ग के लोग दिखते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में जाति की चर्चा पीछे छूट जाती है। खास दल के खास जातीय आधार की मान्यता के बीच से उसी जाति के बीच से जब कुछ आवाजें बिहार के पक्ष में उस दल विशेष के विरोध में उभरती हैं तो बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों को हैरत होती है। यह बदलाव प्रशांत किशोर की राजनीति का कमाल कहा जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर के पीछे समूचा बिहार उठ खड़ा हुआ है। दकियानुसी की हद तक जाति और ध र्म के खेमे में बंट चुकी बिहार की राजनीति की इस सोच में इस बार के चुनावों में खरोंच लगती दिख रही है। इस लिहाज से प्रशांत किशोर, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिहार की सोच में बदलाव की यह बयार बनी रही तो तय मानिए, बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

समावेशी विकास का उत्तराखंड मॉडल

एस. सुनील

भारत में विकास के कई मॉडल की चर्चा होती है। सबकी अपनी खूबियां हैं और अपने अपने राज्य के हिसाब से उनका महत्व और उपयोगिता है। आमतौर पर विकास के मॉडल के तौर पर बड़े राज्यों की चर्चा की जाती है, जिनका सकल घरेलू उत्पाद बहुत बड़ा होता है या जहां औद्योगिकरण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। छोटे और पहाड़ी राज्य ऐसी चर्चा से बाहर हो जाते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों में विकास के एक मॉडल के तौर उत्तराखंड का उदय एक बड़ी परिघटना है। मुश्किल पारिस्थितिकी और निरंतर प्रकृति की मार झेल रहे उत्तराखंड ने समावेशी विकास का एक नया मॉडल विकसित किया है। वहां धर्म और न्याय के साथ विकास का क्रम चल रहा है। वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है, जहां श्कंकड़ कंकड़ शंकर हैय। कदम कदम पर तीर्थ हैं और पवित्र भूमि है। शंकराचार्य का स्थापित किया हुआ बद्रीनाथ धाम है तो सबसे जाग्रत महादेव का केदारनाथ मंदिर भी है। पूरे देश के चार धामों में से एक धाम उत्तराखंड में है तो इसका अपना चार धाम भी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री भी हैं। आदि शंकराचार्य ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए रामेश्वरम और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। उत्तराखंड से लोग गंगा जल लेकर रामेश्वर जाते हैं तो रामेश्वरम से लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह अनोखी विशेषता इस राज्य को एक अलग पहचान देती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड की प्रगति को नई दिशा और नए आयाम दिए हैं। उन्होंने एक सतत और टिकाऊ विकास का अपना स्वदेशी मॉडल विकसित किया है। इसमें तीर्थाटन की अर्थव्यवस्था को विकसित करना एक आयाम है तो प्राकृतिक संसाधनों के जरिए राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास एक दूसरा आयाम है। राज्य सरकार ने प्रकृति और पारिस्थितिकी का संरक्षण करते हुए उद्योग धंधे विकसित करने के नए प्रयास भी किए हैं। समावेशी, टिकाऊ और पारिस्थितिकी से संतुलन के साथ विकास की गति बढ़ाने के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अलग अलग उद्योग समूहों के साथ 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को ध रातल पर उतारा जा चुका है। सरकार की ओर से आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में मिले प्रस्तावों को तत्परता के साथ धरातल पर उतारा जाता है। सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के मामले में अपनी श्रेणी के ज्यादातर राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आधिकारिक आंकडों के मुताबिक आर्थिक प्रबंधन के मामले में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। उससे आगे सिर्फ गोवा है। उत्तराखंड की श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि राज्य का वार्षिक बजट एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। राज्य के आकार और आबादी को देखते हुए यह एक बड़ा मील का पत्थर है। राज्य सरकार ने पारिस्थितिकी के साथ संतुलन बनाते हुए हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज और कोटद्वार में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। इसके अलावा काशीपुर में एरोमा पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी विकसित किया गया है। सरकार खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित कर रही है। राज्य सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के अनुरूप लघु, सूक्ष्म व मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लागू की हैं। सरकार 50 नए एमएसएमई कलस्टर बना रही है और साथ ही स्टार्टअप की नई नीति लेकर आई है। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ सरकार लॉजिस्टिक्स पर भी काम कर रही है ताकि राज्य में आने वाले उद्योग समूहों को किसी किस्म की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक व आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक व मानव विकास पर भी समान रूप से ध यान दिया है। उन्होंने समाज के वंचित व हाशिए पर के समूहों को मुख्यधारा में लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और हर उम्र वर्ग के नागरिकों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उत्तराखंड में सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए घर पर ही वेरिफिकेशन की सुविधा दी है। इसी तरह वृद्ध व निरुशक्त जनों के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1.64 लाख से अधिक मातृशक्ति को सशक्त बनाने का कदम उठाया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को तीन लाख और महिला स्वंय सहायता समूहों यानी एसएचजी को पांच लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने नव प्रसूता के लिए महालक्ष्मी किट की योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु को पोषण व स्वच्छता का सामान प्रदान किया जाता है। इस किट में शिशु के लिए सूती टोपी, जुराब, लंगोटी, तौलिया, शिशु साबुन, रबर शीट, कंबल, टीकाकरण कार्ड जैसी चीजें शामिल होती हैं। इसके माध्यम से नव प्रसूता और बच्चे दोनों की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याण की समस्त योजनाओं को बेहद प्रभावी तरीके से उत्तराखंड में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के 60 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के नौ लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 55 हजार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 18,602 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक व मानव विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार सनातन के संरक्षण और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा व संवध ान के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। यह अनायास नहीं है कि समान नागरिक कानून लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर समान नागरिक कानून बनाया गया। अब उत्तराखंड के बनाए कानून के अनुरूप ही देश के दूसरे राज्यों में समान नागरिक कानून का मसौदा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड को ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराना वादों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने का सौभाग्य मिला।

पहाड़ों में हुई बर्फबारी से प्रदेश में मौसम ने लिया यू-टर्न, इन जिलों का पारा 20 डिग्री के नीचे आया

लखनऊ, (संवाददाता)। मौसम विभाग ने 13 अक्तूबर को मानसून की विदाई की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ठंड ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और ठंडी पछुआ हवाओं के असर से दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेशभर में न्यूनतम पारे में गिरावट देखने को मिली है, साथ ही सुबह शाम की हवा सिहरन भरी होने लगी है। दोपहर की धूप में तपिश कम हुई है।सोमवार को कानपुर शहर और बाराबंकी में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 16 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी समेत लगभग 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की संपूर्ण वापसी हो गई है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं हैं। साथ ही दिन व रात के तापमान के सामान्य या इससे थोड़ा कम रहने के संकेत हैं।, लाहौल–स्पीति की चंद्राघाटी में गोंदला के सामने लगती पहाड़ियों से मौसम साफ होते ही हिमस्खलन होना शुरू हो गया है। शनिवार को दोपहर बाद पहाड़ी से अचानक हिमस्खलन हुआ। हालांकि, इससे क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अगले 4–5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जबकि अधिकतम तापमान में धीरे–धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मनाली–लेह मार्ग पर वनवे वाहनों की आवाजाही जारी है। शनिवार को लेह से मनाली की तरफ वाहनों को छोड़ा गया। वहीं दारचा में फंसे करीब 300 ट्रकों में से 150 को लेह के लिए भेजा गया। 150 ट्रक दारचा में रुके हैं। गोंदला के प्रधान सूरज ठाकुर ने बताया कि गोंदला के वामतट रालिंग गांव के पास से यह हिमस्खलन हुआ है। राजधानी में अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में मौसम ने एकदम से करवट लिया है। सोमवार को दिन में धूप की वजह से पारे में 1.2 डिग्री की बढ़त के साथ हल्की गर्मी रही, जबकि रात का पारा लुढ़ककर 18 डिग्री के आसपास ठहर गया। बीते दो दिनों से रात से सुबह के बीच लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। तापमान में इस उतार चढ़ाव से लोगों को सर्दी–जुकाम जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक लखनऊ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के सामान्य या इससे नीचे रहने की संभावना है। सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री की बढ़त के साथ 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का पारा 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

सस्ती और प्रभावी दवाएं तलाशकर आगे बढ़ेगा भारत

लखनऊ, (संवाददाता)। केंद्रीय औषधि विभाग के सचिव डॉ. अमित अग्रवाल के मुताबिक सस्ती और प्रभावी दवाएं तलाशकर ही अपना देश विश्व के दवा उद्योग में और बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। डॉ. अमित अग्रवाल ने सोमवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर) रायबरेली के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में हुए दीक्षांत समारोह में पांच मेधावियों को पदक और 115 छात्र–छात्राओं को उपाधि दी गईं। मुख्य अतिथि के कहा कि भारत का दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खासकर जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में। प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अब हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है जैसे कि नए मॉलीक्यूल्स, बायोलॉजिक्स और मेडिकल डिवाइस के विकास और नवाचार पर ध्यान देना होगा। समारोह के विशिष्ट अतिथि बीबीएयू के वाइस चांसलर प्रो. राज कुमार मित्तल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाईपर–रायबरेली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्ष डॉ. मधु दीक्षित ने की। संस्थान के निदेशक प्रो. शुभिनी ए. सराफ ने शैक्षणिक वर्ष 2024–2025 की संस्थान की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नाईपर–रायबरेली का संचालन लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित एक ट्रांजिट परिसर से किया जा रहा है। संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण का पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। निर्माण पूरा होने पर इसका संचालन मुख्य परिसर में किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

बच्चों को नवाचार प्रोजेक्ट के बारे में बताया

लखनऊ, (संवाददाता)। कल्ली पश्चिम स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विकसित भारत बिल्डाथॉन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हुआ। इस दौरान बच्चों को नवाचार प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। एडी बेसिक श्याम किशोर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ ही खेल, नई सोच व नवाचार का विकास होगा। कार्यक्रम में बीएसए रामप्रवेश मौजूद रहे। इसी तरह बीकेटी परिषदीय विद्यालय में भी कार्यक्रम हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थी अपनी चुनी गई थीम पर अपने विचार व उत्पाद को विकसित कर पाएंगे। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी धमेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक राकेश कुमार, शिक्षक अनुराग सिंह राठौर व अन्य मौजूद रहे।

सफल प्रशिक्षु महिलाओं को दिए प्रमाण पत्र

लखनऊ, (संवाददाता)। श्री हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय चारबाग का 64वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। अस्पताल के निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफल प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि श्री हरभज राम कृपा देवी अस्पताल गरीबों, वंचितों को मुफ्त इलाज, परामर्श व दवाई दे रहा है। साथ ही सिलाई कढ़ाई ,कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसा कौशल निशुल्क दे रहा है। इसके लिए अस्पताल के अध्यक्ष विद्यासागर गुप्ता, सचिव अमित गुप्ता, वाइस चेयरमैन रमेश अग्रवाल एवं समस्त ट्रस्टी बधाई के पात्र है। कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ ट्रस्टी सुशील अग्रवाल, सिद्धार्थ गुप्ता और समाजसेवी राजेंद्र सिंह बग्गा मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना न्यायपालिका की गरिमा पर हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के विरोध में मार्च निकाल रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परिवर्तन चौक पर रोक दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर घटना को न्यायपालिका की गरिमा और सांविधानिक मूल्यों पर सीधा हमला बताते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना मांगपत्र भी प्रेषित किया। डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता परिवर्तन चौक पर एकत्र हुए, जो हजरतगंज स्थित डॉ. आंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकालना चाह रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। महासंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि सांविधानिक संस्थाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में रामचंद्र पटेल, पीसी कुरील, अशोक कुमार, शैलेंद्र अंबेडकर, सीएल राजन, जेपी वर्मा, कमलाकांत गौतम, पंकज प्रसून, नेकराम बौद्ध, संतराम, बीपी सिंह, ए. रहमान, इदरीश सिद्दीकी, सियाराम गौतम, बिमला बौद्ध, डॉ. सत्यवती दोहरे, डॉ. संघमित्रा, सोनम गौतम, पंडित प्रदीप पासी, अभय प्रताप त्यागी आदि शामिल रहे।

एआई टीवी की बढ़ रही डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में हर महीने 1000 से अधिक टीवी की हो रही बिक्री

लखनऊ, (संवाददाता)। जिस टीवी को कभी बुद्ध बक्सा कहा जाता था, वो तकनीक के बदलते दौर में अब स्मार्ट और कृत्रिम बुद्धि (एआई) वाला बन गया है। ये एआई टीवी न केवल इंटरनेट से जुड़कर

अनगिनत डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच दे रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। आज हर हाथ में मोबाइल और हर घर में डिजिटल स्क्रीन जरूर है, फिर भी टेलीविजन का आकर्षण कम नहीं हुआ है। राजधानी के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक बाजार में हर महीने एक हजार से अधिक एआई फीचर वाले स्मार्ट टीवी की बिक्री हो रही है। दुकानदारों के अनुसार, धनतेरस और दिवाली पर बिक्री में 30 से 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। नाका बाजार के टीवी विक्रेता अखिलेश शर्मा बताते हैं कि मनोरंजन के साधन जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन टीवी की मांग में कमी नहीं आई। शादी–व्याह, त्योहार या सामान्य दिनों में भी लोग नई तकनीक वाले टीवी खरीद रहे हैं। कंपनियां समय–समय पर फीचर बदल रही हैं, जिससे ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। 60 वोल्ट में भी चलेगी एआई टीवी जहां पहले टीवी को चलाने के लिए 200–250 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती थी, वहीं अब 60 वोल्ट में भी आधुनिक टीवी आसानी से चल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉल के एक विक्रेता के मुताबिक, अब टीवी की साउंड सिनेमा हॉल जैसी और पिक्चर क्वालिटी बेहद रियलिस्टिक हो गई है। ग्राहक इन खूबियों से आकर्षित हो रहे हैं। एलईडी टीवी में अब ऑटोमैटिक ब्राइटनेस फीचर मौजूद है, जो दिन और रात के हिसाब से स्क्रीन की रोशनी व कलर को खुद समायोजित करता है। डीजे जैसी साउंड क्वालिटी और सिनेमा हॉल का अहसास देने वाले फीचर्स ने इसे और खास बना दिया है। अब टीवी को सीसीटीवी कैमरे से जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा और मनोरंजन... दोनों जरूरतें पूरी हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई आधारित टीवी घरेलू गैजेट्स से जुड़कर स्मार्ट होम सिस्टमश का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में टेलीविजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली का प्रतीक बनता जा रहा है।

किसान व फैशन डिजाइनर के बच्चों को मिले तीन–तीन स्वर्ण पदक

लखनऊ, (संवाददाता)। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज मंगलवार को आयोजित किया गया। दीक्षांत की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी और मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली ने मेधावियों का उत्साह बढ़ाया। इस बार कुल 146 पदकों में 99 छात्राओं और 47 पदक छात्रों मिले। इससे पहले कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लैब से लेकर फैकल्टी और एमओयू के बारे में जानकारी दी। इस बार के दीक्षांत के मौके पर सबसे अधिक मेडल पाने वाले रहमाना के पिता फैशन व डिजाइनर हैं। जबकि धर्मेश यादव के पिता किसान हैं। जबकि अर्पूव द्विवेदी के पिता इंजिनियर हैं। इनको तीन–तीन स्वर्ण पदक मिले हैं। इसके अलावा तनु प्रिया को दो स्वर्ण पदक दिए गए। इसके साथ ही इस बार दो नए मेडल डोरी लाल सागर मेमोरियल स्वर्ण पदक और इतिहास में रामपति देवी स्वर्ण पदक भी छात्रों को दिए गए। इसके आलावा समारोह में कुल 1424 डिग्रियां दी गई। दीक्षांत के मौके पर रहमाना ने बताया की उन्हें उर्दू, अरबी फारसी, कला एवं मानविकी संकाय और बीए उर्दू में प्रथम आने पर मुझे तीन स्वर्ण पद मिलें हैं। पिता इजहार सिद्दीकी फैशन डिजाइनर और मां सुमैया गृहिणी हैं। रहमाना ने कहा मेरा सपना है जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूं, वहीं प्रोफेसर बनूं। दीक्षांत के मौके पर अपूर्व द्विवेदी ने बताया उन्होंने अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय और बीटेक में प्रथम आने पर तीन स्वर्ण पदक मिलें हैं। वह आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहें हैं। अपूर्व ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है। पिता हरिकेश द्विवेदी शिक्षक और मां सरोज द्विवेदी गृहिणी हैं। दीक्षांत में धर्मेश यादव ने बताया स्नातक स्तर पर सभी संकाय में प्रथम, विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने व बीएससी–रसायन में प्रथम आने पर तीन स्वर्ण पदक उन्हें मिलें हैं ।

संक्षिप्त खबरें

गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गौ जन्य उत्पादों का प्रोत्साहन

लखनऊ,उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गौ जन्य उत्पादों के प्रचार–प्रसार को सशक्त करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से दीपावली के दृष्टिगत गाय के गोबर से बने दीप, मूर्तियां और अन्य उत्पादों के उपयोग के लिए जनमानस में व्यापक जागरूकता फैलाने एवं इन उत्पादों की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को गौजन्य उत्पादों के उत्पादन और विपणन में प्रोत्साहित किया जाए और उनका पूर्ण सहयोग लिया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक जनपद में एक आदर्श गोशाला स्थापित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'काऊ टूरिज्म' की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।धर्मपाल सिंह ने बैठक में कहा कि गोवंश का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उनका उद्देश्य केवल गोशालाओं को संरक्षण देना नहीं, बल्कि गौजन्य पदार्थों के व्यवसायिक उपयोग से गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना भी है।बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मेश्राम ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोबर और गोमूत्र के व्यवसायिक उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जाएं और लोगों को इससे जोड़ा जाए।इस अवसर पर पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पाण्डेय, प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्र, निदेशक प्रशासन एवं विकास योगेन्द्र पवार, मुख्य कार्यकारी उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग प्रमोद कुमार सिंह और संयुक्त निदेशक पी.के. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इंस्पायर मानक योजना के तहत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता लखनऊ में प्रारम्भ

लखनऊ, (संवाददाता)। इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट तीन दिवसीय प्रतियोगिता लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान–भारत और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रारम्भ हुई। प्रतियोगिता का शुभारम्भ संयुक्त शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल ने किया।मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोटोटाइप मॉडल और प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हुए छात्रों से उनके मॉडल के विषय में संवाद किया। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रचनात्मक और नवीन सोच को बढ़ावा देना, छात्रों को अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उनके मौलिक और नवाचारपूर्ण तकनीकी विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है।प्रतियोगिता के पहले दिन वर्ष 2023–24 में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित कुल 108 छात्र–छात्राओं ने अपने प्रोटोटाइप मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। ज्यूरी ने राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट 11 मॉडल और प्रोजेक्ट का चयन किया।

बार-बार बुलाना गुजरा नागवार, नर्स ने लगा दिया गलत वीगो

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीज को वीगो लगाने के लिए बार–बार बुलाना नर्स को नागवार गुजर गया। नर्स का पारा इतना चढ़ा कि उसने गुस्से में गलत वीगो लगा दिया। तीमारदार उससे मरीज का हाथ सूजने की बात बताते रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला का हाथ काटने की नौबत आ गई है। केजीमयू के हड्डी रोग विभाग में लखनऊ निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला केसरी करीब एक महीने से भर्ती हैं। घटना पिछले सप्ताह की है। मरीज के घरवालों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स से वीगो लगाने के लिए कहा। कई बार कहने के बाद भी जब नर्स ने वीगो नहीं लगाया तो तीमारदार उसके केबिन के सामने ही बैठ गए। इसके बाद गुस्से में नर्स ने वीगो लगा दिया। वीगो लगाने के बाद महिला के हाथ में सूजन आ गई। तीमारदार ने नर्स से हाथ ने सूजन आने की बात बताई, लेकिन वह दोबारा नहीं आईं। इसकी वजह से हाथ काला पड़ गया। ड्यूटी बदलने पर दूसरी नर्स ने बताया कि वीगो गलत लग गई थी, इसी वजह से सूजन आ गई है। आशंका है कि गलत वीगो की वजह से महिला का हाथ काटना पड़ सकता है। मामले की शिकायत मिलने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने जांच समिति बना दी है। ग्लत वीगो लगने से अगर हाथ काला पड़ जाए तो उसे काटना भी पड़ सकता है। इस मामले की शिकायत मिली है। शिकायत के बाद जांच समिति बनाई गई है। जांच में दोषी मिलने पर आरोपी नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आलू किसानों के लिए खुशखबरी विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट

लखनऊ, (संवाददाता)।प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश के आलू किसानों के हित में विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट देने का निर्णय लिया गया।उद्यान मंत्री ने बताया कि वर्तमान वर्ष में विभागीय आलू बीज की विक्रय दरें उत्पादन लागत के आधार पर 2760 से 3715 रुपये प्रति कुंतल तय की गई थीं, जबकि निजी बीज कंपनियों की औसत दरें 2500 से 3500 रुपये के बीच हैं। नए निर्णय के अनुसार किसानों को गुणवत्तायुक्त सभी श्रेणी के विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट मिलेगी। शोध संस्थाओं और सरकारी संस्थानों को यह लाभ लागू नहीं होगा। इसके बाद सभी विभागीय बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति कुंतल के बीच रहेंगी।मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों को आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा और गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता से प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जनपदों में यह लाभ शीघ्र किसानों तक पहुंचाया जाए और बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तथा समयबद्ध रूप से संपन्न कराई जाए।वर्तमान वर्ष में उद्यान विभाग के पास 41,876 कुंतल आलू बीज भंडारित हैं। यह बीज नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा,।

जब तक मुआवजा तय नहीं होता, एक इंच जमीन नहीं देंगे'

लखनऊ, (संवाददाता)। विकास प्राधिकरण (एलडीए) की वरुण विहार आवासीय योजना पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन (लोकतांत्रिक) के बैनर तले मोहान रोड स्थित सलेमपुर पतौरा मोड़ पर सोमवार को हुई बैठक में 12 गांवों के किसानों ने एलडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्राम भालिया, आदमपुर, इंदवारा, बहरू, जलियां मऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नटकौरा, तेज किशन, दोना, रेवरी और सकरा के जुटे किसानों ने कहा कि जब तक लिखित समझौता और पूरा मुआवजा तय नहीं होता, तब तक एक इंच जमीन नहीं देंगे। बैठक में पहुंचे एलडीए के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा कि एलडीए ने पहले भी गोमतीनगर, राजाजीपुरम, जानकीपुरम और बसंत कुंज योजनाओं में किसानों के साथ दोहरे मापदंड अपनाए। कहीं मुआवजे में भेदभाव किया गया, तो कहीं विरोध करने पर गोलियां चलीं। सीतापुर रोड योजना में दो किसानों की मौत और बसंत कुंज योजना में कई घायल हुए थे। अब किसान दोबारा शोषण के खिलाफ लामबंद हैं। बीते 21 अगस्त को किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें 16 प्रमुख मांगें रखी गईं थीं, जिसमें बढ़ा हुआ डीएम सर्किल रेट, संपूर्ण मुआवजा, 5: भूमि वापसी, मुफ्त भूखंड, रोजगार, स्कूलों का आधुनिकीकरण और हाउस टैक्स से राहत जैसी मांगें शामिल थीं। नायब तहसीलदार तुलसीराम ने मंच से सभी किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की मांगों का ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेज कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम लोधी, युवा जिला अध्यक्ष अमित यादव समेत अन्य कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

26 लाख दीपों और डिजिटल संकल्प के साथ भव्य आयोजन तैयार

लखनऊ, (संवाददाता)। भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या दिव्यता और भक्ति के आलोक से एक बार फिर जगमगाने को तैयार है। दीपोत्सव–2025 के भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष आयोजन में 26 लाख से अधिक दीपों के प्रज्ज्वलन और 2100 श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक महाआरती के साथ दो नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे, जिसका साक्षी देश–दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु बनेंगे।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से 'एक दीया राम के नाम' अभियान के तहत वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्रीराम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। इस पहल से दीपोत्सव वैश्विक स्तर पर और अधिक समावेशी बन गया है। डिजिटल संकल्प के माध्यम से श्रद्धालु अपने प्रियजनों के लिए मंगलकामनाएं भी भेज सकते हैं।मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि श्री रामजन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से विश्वभर के श्रद्धालु डिजिटल रूप से दीपोत्सव–2025 में शामिल हो सकते हैं। ऐप पर श्रद्धालुओं के लिए तीन प्रकार के पैकेज उपलब्ध हैं। श्रम ज्योति पैकेज 2100 रुपए में है और इसमें रोली, सरयू जल, अयोध्या रज, रामदाना, मिश्री, रक्षा सूत्र, हनुमान गढ़ी के लड्डू और चरण पादुका शामिल हैं। सीता ज्योति पैकेज 1100 रुपए में माता सीता को समर्पित है, जिसमें रोली, सरयू जल, रामदाना, रक्षा सूत्र और हनुमान गढ़ी के लड्डू शामिल हैं। लक्ष्मण ज्योति पैकेज 501 रुपए में भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पराक्रम और सेवा भाव को समर्पित है, जिसमें रोली, अयोध्या रज, रामदाना, रक्षा सूत्र और मिश्री शामिल हैं। ऑनलाइन संकल्प पूर्ण करने पर ये पवित्र प्रसाद सीधे श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाए जाएंगे।दिव्य अयोध्या एक पर्यटन आधारित मोबाइल एप्लिकेशन एवं वेब पोर्टल है, जिसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना से ग्रामीण अंचलों में ऊर्जा और आय का नया मॉडल स्थापित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गोवर्धन योजना ने अब नई दिशा और रोशनी लेकर आई है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 72 जिलों में बायोगैस टैंक स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की गई है। अब तक 117 में से 115 बायोगैस संयंत्र पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, जहां से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों की आमदनी के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।श्रावस्ती जनपद की टंडवा महंत ग्राम पंचायत इस योजना की सफलता का सशक्त उदाहरण है। यहां 24 लाख रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट ने गांव की ऊर्जा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बना दिया है। इस प्लांट से संचालित आटा चक्की पूरी तरह बायोगैस से चल रही है, जो प्रतिदिन 2 से 3 क्विंटल गेहूं पीसने में सक्षम है। पहले जहां चक्की के संचालन में बिजली और डीजल पर निर्भरता थी, वहीं अब ग्रामीणों को केवल 1 रुपये प्रति किलो की दर पर पिसाई सुविधा उपलब्ध है। इससे ग्रामीणों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।बायोगैस संयंत्रों में गोबर और जैविक कचरे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ जैविक खाद का निर्माण भी संभव हुआ है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई और खेती अधिक टिकाऊ बनी है।योजना के संचालन में स्थानीय युवाओं को बायोगैस यूनिट के रखरखाव एवं संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि महिलाएं खाद निर्माण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। इस प्रकार यह योजना रोजगार, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरताकृतीनों लक्ष्यों को एक साथ पूरा कर रही है।टंडवा महंत ग्राम पंचायत में स्थापित सोलर प्लांट से अब तक 51,151 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की जा चुकी है, जो पंचायत के विकास कार्यों में उपयोग की जा रही है। इसी प्रकार बायोगैस से चलने वाली चक्की से 2,100 रुपये की आय दर्ज की गई है, जिससे पंचायत को स्थायी आर्थिक आधार प्राप्त हुआ है।पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि "टंडवा महंत ग्राम पंचायत का बायोगैस प्लांट आत्मनिर्भरता और नवाचार का जीवंत उदाहरण है। यह न केवल ऊर्जा बचत कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों को निश्चित आय और समय की बचत भी प्रदान कर रहा है। यह मॉडल 'ऊर्जा से आय' की दिशा में राज्य के लिए प्रेरक है।"पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक बायोगैस इकाइयाँ केवल ऊर्जा उत्पादन का माध्यम नहीं हैं, ।

दस्तक अभियान संबंधित गतियों को शत-प्रतिशत संपादित करें, कोई भी घर न छुटे - डॉ लक्ष्मी सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 लक्ष्मी सिंह ने ब्लॉक सिरकोनी के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में दस्तक, संचारी रोग नियंत्रण अभियान संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव, सहायक मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा, बीसीपीएम सचेंद्र चौहान, संगिनी मीना यादव, एएनएम विनीता देवी, आशा गुंजन देवी उपस्थित रहकर अपनी अपनी गतिविधियां संपादित करते हुए मिले। मुख्य चिकित्साधिकारी ने जनसमुदाय से सीधे संवाद कर दस्तक, संचारी अभियान संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी लीं और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दीं। उन्होंने आशा, संगिनी और बीसीपीएम को निर्देशित किया कि दस्तक अभियान संबंधित गतियों को शत–प्रतिशत संपादित करें, कोई भी घर न छुटे, फीवर सर्वे, संभावित मरीजों की तत्काल जांच कराएं, लोगों को हाथ धोने, मच्छरदानी का प्रयोग करने, जल जमाव न होने देने, जलपात्रों को खाली करते रहने, साफ–सफाई रखने आदि के प्रति जागरूक करें। हर स्तर से कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करें। जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत अब तक शिक्षा विभाग द्वारा 1483 रैलियां निकाली जा चुकी हैं, पंचायती राज विभाग द्वारा 691 स्थानों पर नालियों की सफाई, 690 स्थानों पर झाड़ियों की कटाई, 388 हैंडपंप का मरम्मत, 363 शौचालयों का निर्माण, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा 5383 नालियों की सफाई, 252 स्थानों पर फागिंग कराई गई, पशुपालन विभाग द्वारा 150 शूकर पालकों को शूकर जनित बीमारियों, शूकर बाड़ों की सफाई, कीटनाशी का उपयोग के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने के प्रति प्रेरित किया गया। कृषि विभाग द्वारा 281 बैठकों के माध्यम से किसानों को चूहे छछूंदर से होने वो बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। आशा द्वारा घर 78879 घरों का सर्वे किया गया जिसमें 146 बुखार वाले व्यक्ति, 106 जुखाम खांसी वाले, 3 टी बी लक्षण वाले, 8 अति कुपोषित बच्चे मिले जिनकी जांच उपचार कराया जा रहा है। आशा द्वारा घर घर भ्रमण के दौरान क्लोरिनेशन डेमो, हाथ धोने की प्रक्रिया का प्रदर्शन, मातृ बैठकों, स्टीकर एवं पोस्टर पेस्टिंग, संचारी हैंडबिल का वितरण, ब्रीडिंग सोर्स रिडक्शन आदि कार्य भी कराया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक डेंगू के 65 मरीज, मलेरिया के 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने संचारी रोगों से बचाव हेतु जनसमुदाय से अपील की है कि आप सब अपने अपने घरों के आस पास साफ सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, बेकार, खाली पड़े जलपात्रों को नष्ट कर दें, नालियों में कूड़ा कचरा न डालें, रुके हुए पानी में जला हुआ मोबिल ऑयल डालें, खुले बदन न सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कुछ भी खाने पीने से पहले, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खुले में शौच न करें, घर पर शौचालय बनवाकर उसका उपयोग करें। बुखार की स्थिति में लापरवाही न करें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच उपचार कराएं, झोलाछाप से इलाज न कराएं। हम सबने यह ठाना है, संचारी रोग मिटाना है। अगर मिले आपका सहयोग, खत्म होगें संचारी रोग।

बीएसए परिसर में यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने किया प्रदर्शन

अयोध्या।विवेक यादव प्रान्तीय अध्यक्ष एवं राजेश चंद्र श्रीवास्तव,महामंत्री,यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को बीएसए कार्यालय पर लम्वित 18 सूत्रीय मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया।इस दौरान प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन कार्यो ने बीएसए लालचंद को 18 सूत्रीय मांगों संबंधित ज्ञापन सौपा।धरने में अजय शुक्ला प्रान्तीय उपाध्यक्ष के साथ साथ हरी कृष्ण श्रीवास्तव मण्डलीय अध्यक्ष,रामबिलास यादव मण्डलीय सचिव,आनन्द यादव जनपद अध्यक्ष, नीरज सिंह जनपद सचिव,निशा मिश्रा जनपद उपाध्

यक्ष,सागर यादव कोषाध्यक्ष,दिनेश कुमार ऑडीटर, अमित तिवारी,धीरज कनौजिया,प्रदीप कुमार, कृपाराम, के0 के0 कनौजिया, जनार्दन यादव, उमाकान्त मिश्रा, मोतीलाल मौर्या, पतिराम, शाजिया रिजवी, राहुल मिश्रा, शत्रुघ्न शुक्ला, आशीष कुमार, विवेक सिंह, प्रियंका पासवान, मधुरेन्द्र श्रीवास्तव, मनोज दूबे, शिवम शुक्ला, शैलेश श्रीवास्तव, सचिन सिंह, मनीष यादव,अंजली चौरसिया, अभय मौर्य, सौरभ यादव सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।

संक्षिप्त खबरें

महिला एसओ ने किया दो दर्जन से अधिक दो पहिया वाहनों का चालान

अयोध्या। महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने दीपावली व अन्य पर्वों को देखते हुए शहर के विभिन्न चौराहों व बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने ऐसे दो पहिया वाहन चालकों पर चालान की कार्यवाही किया जो एक ही वहां पर तीन लोग सवार थे और साथ ही साथ हेलमेट नहीं धारण किए हुए थे।इस मौके पर उन्होंने दो पहिया वाहन चालकों से कहा कि आप लोग पुलिस की डर से नहीं बल्कि अपने जान की रक्षा के लिए तथा अपने परिवार के लिए हेलमेट धारण करें और यातायात के नियमों का पालन करें।क्योंकि जब आप घर से

बाहर निकलते हैं तो आपके परिवार वालों को आपकी पहुंचने का बेसब्री से इंतजार रहता है।इसलिए आप सभी दो पहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें।उन्होंने चौक रिकाबगंज गुदरी बाजार की अलावा अन्य प्रमुख चौराहों पर यह चेकिंग अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने शहर के चौक,रिकाबगंज व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया।इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद खासकर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति एहसास कराया कि पुलिस आपके साथ है आपको किसी से भयभीत होने की जरुरत नहीं है।इस मौके पर महिला थाना।

शत–प्रतिशत कराये जोड़ो का सत्यापन, अन्यथा होगी कार्यवाही – जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

प्रस्तावित बदलापुर महोत्सव जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्र जोड़ो का विवाह कराया जाना है। आवेदको से ऑनलाईन आवेदन लिया जा रहा है, जिसकी जॉच हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी (नगर पालिकाध्नगर निकाय) जौनपुर के पोर्टल पर अग्रसारित कर दिये गये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि अग्रसारित आवेदन पत्रों की जॉच शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करने के साथ ही आवेदक की पात्रता की जाँच गहनता से करते हुए आवेदको द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातो का परीक्षण कराये, सत्यापन के पश्चात भी अपात्रता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस मुठभेड़ में दो अपराधी गिरफ्तार एक के पैर में लगी गोली

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मीरगंज व मुगराबादशाहपुर की संयुक्त पुलिस टीम के साथ मंगलवार रात बदमाशो की मुठभेड़ हुई,मुठभेड़ में दो बदमाशो के के पैर में गोली लगी है।इस संबंध

में बुधवार को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अपराधी किस्म के लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के।नियत से जा रहे है। मुखबिर की सूचना पर सेमरी पुलिया अंडरपास से आगे पुलिस ने घेरा बंदी किया इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की तरफ से किए गए फायरिंग में मुठभेड़ में आसिफ पुत्र कल्लू निवासी मोहद्दीनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ व ,कविनाश पुत्र प्यारेलाल हरिजन निवासी मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ को पुलिस की जबाबी फायरिंग में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। घेराबन्दी में दो अन्य बदमाश नूर आलम पुत्र लियाकत अली निवासी मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ व मुदस्सिर पुत्र अयूब नि0 मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पिकअप, नकदी, तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों घायलों के खिलाफ 13 व 08 मुकदमें अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज है। घायलों को उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।पकड़े गए बदमाशो के पास से एक पिकअप,तमंचा,दो जिंदा व खोका कारतूस तथा कुछ नगद रुपए बरामद हुआ है

एक साल में ही जलजीवन मिशन टंकी की बाउण्ड्री गिरकर हुई धाराशाही

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। जिले के सिरकोनी विकास क्षेत्र के समोपुर गांव में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पानी टंकी लगाई बनायी गई है। उक्त जल निगम पानी टंकी की बाउण्ड्री लगभग पांच माह पूर्व बनी हुई थी, जो अब टूटकर पूरी तरह से धराशाई हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त योजना के जिम्मेदारों द्वारा मानक को ताख पर रखकर चहारदीवारी बनवायी गई थी। जो की साफ दिखाई दे रहा है कि एक वर्ष भी नहीं बीता कि बाउंड्री टूटकर धराशाही हो गयी है। देखा जाए तो जहां एक तरफ सरकार तमाम योजनाओं को चलाकर ग्रामीणों को कई प्रकार की सुविधा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इस विभाग के संबंधित लोगों द्वारा सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पलीता लगाये हुए हैं जिसका जीता जागता प्रमाण लोगों के सामने पड़ा हुआ है। यहां तक कि बाउंड्री गिरने के काफी दिन बीत जाने के बावजूद आज तक विभागीय लोगों द्वारा बाउण्ड्री को ठीक नहीं कराया गया। इस बाउण्ड्री के प्रति विभागीय लोग पूरी तरह से कुम्भकर्णी निद्रा में लीन पड़े हुए हैं। आखिर इस प्रकार की समस्या का जिम्मेदार कौन है।

संक्षिप्त खबरें

कोर्ट परिसर में अधिवक्ता पर धारदार हथियार से हमला, दरोगा भी घायलव्य दो आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत, (संवाददाता)। पीलीभीत के कोर्ट परिसर में मंगलवार सुबह अधिवक्ता पर बांके से हमला कर दिया गया। उन्हें बचाने पहुंचे दरोगा भी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं, पुलिस ने हमला करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में नामजद अधिवक्ता ओमपाल निवासी गांव खरदाई (थाना दियोरिया) मंगलवार को मुकदमे की तारीख पर कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान मुकदमे के दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और अचानक बांके से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में अधिवक्ता ओमपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बचाने पहुंचे कोर्ट परिसर में तैनात दरोगा अरविंद त्यागी भी बांके के प्रहार से घायल हो गए। घटना से कचहरी परिसर में अफरा–तफरी मच गई। दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर एसपी अभिषेक यादव भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि हमला करने के आरोपी कचहरी के पीछे खुले रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। बांका छिपाकर लाए थे। घायल अधिवक्ता बीसलपुर में प्रैक्टिस करता है और हत्या के एक मुकदमे में आरोपी है। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पर्व को लेकर तैयारी पूरी, यात्रियों को जागरूक करेंगे परिचालक

पीलीभीत, (संवाददाता)। दीपावली को लेकर परिवहन विभाग के अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह यात्रियों को जहर खुरानी गिरोह को लेकर जागरूक करेंगे, जिससे उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। दूर–दराज क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसको लेकर चालक–परिचालकों को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। अफसरों ने निर्देश दिए हैं कि त्योहार होने पर बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। ऐसे में जहरखुरानी गिरोह भी सक्रिय हो जाते हैं। यात्रा के दौरान वह लोग उन्हें नशा देकर यात्रियों के साथ सामान लूट लेते हैं। ऐसे में परिचालक बस संचालन से पूर्व यात्रियों को जागरूक करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई यात्री इसका शिकार होता है, तो चालक–परिचालक पुलिस से संपर्क कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराएंगे। इसके साथ ही उनके परिवार से संपर्क करेंगे। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि चालक–परिचालकों को त्योहार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुगम सफर कराया जा सके।

50 फीसदी केंद्रों पर अभी तक शुरू नहीं हुई धान की तौल

पीलीभीत, (संवाददाता)। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते मंडी परिसर के 50 फीसदी केंद्रों पर 13 दिन बाद भी धान की तौल शुरू नहीं पाई है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बंद केंद्रों के सामने धान सुखाने के लिए डाल रखा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर मंडी परिसर में विभिन्न एजेंसियों के 33 धान क्रय केंद्र पहली अक्तूबर को खोले गए थे।

दिव्यांग होकर भी रिहान ने दी हौसलों को नई उड़ान

पीलीभीत, (संवाददाता)। ब्लॉक ललौरीखेड़ा के ग्राम गोंच निवासी दिव्यांग क्रिकेटर रिहान अहमद ने अपने जज्बे और प्रतिभा से जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया है। हाल ही में देहरादून में 21 से 27 सितंबर तक आयोजित भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के ट्रायल में रिहान का चयन हुआ है। अब वह 13 से 17 नवंबर तक श्रीलंका में होने वाली पांच मैचों की अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हिस्सा लेंगे। ग्राम गोंच निवासी रिफाकत हुसैन के पुत्र रिहान दिव्यांग हैं। उन्होंने कभी अपने सपनों को सीमाओं में कैद नहीं होने दिया। रिहान की गेंदबाजी राइट हैंड मध्यम तेज है। इसी हुनर ने उन्हें प्रदेश की टीम तक पहुंचाया था। वर्ष 2023 में उनका चयन उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ था और तब से वे लगातार अपने खेल से सबका दिल जीत रहे हैं। रिहान का कहना है भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम से खेलना मेरा सौभाग्य है। अब तमन्ना है कि मेरा प्रदर्शन देश का मान बढ़ाए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाई रिजवान हुसैन को दिया है, जिन्होंने हर मुश्किल समय में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने रिहान पिछले पांच साल से बरेली के डोरी लाल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। उनकी लगन और मेहनत ने कई पुरस्कार दिलाए हैं। अब जब वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रहे हैं, तो गांव और जिले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिहान ने बताया कि वे 12 नवंबर को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना होंगे।

नहर कोठी की छत पर मिला युवक का शव

सीतापुर, (संवाददाता)। कस्बे में नहर कोठी की छत पर सोमवार को एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने शव की शिनाख्त अनुराग वर्मा के रूप में की। परिजनों के अनुसार युवक सोमवार सुबह संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। कोतवाली पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं। क्षेत्राधिकारी महोली नागेंद्र चौबे ने बताया कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। यदि वह कोई आरोप लगाते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। परिजनों के अनुसार उरदौली निवासी अनुराग वर्मा (21) सोमवार सुबह करीब 7 बजे घर से निकले थे। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ग्रामीणों व पुलिस ने गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर नहर कोठी की छत पर एक शव पड़ा होने की सूचना दी। मौके पर उन्होंने शव की शिनाख्त की। ग्रामीणों के अनुसार युवक का रिश्तेदारी में एक महिला से प्रेम–प्रसंग चल रहा था। शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर दिलीप कुमार चौबे ने बताया कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार चार माह पहले भी युवक ने एक युवती के चक्कर में अपने हाथ की नस काट ली थी। परिजनों ने युवक का उपचार करवाया था। इसके बाद से वह लगातार युवती के संपर्क में था। इस रिश्ते को लेकर युवक तनाव में भी रहता था। वहीं, कुछ ग्रामीण युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी किए जाने की चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है।

दस वर्ष पहले जर्जर हो चुकी है नहर कोठी की इमारत

स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर युवक का शव पड़ा मिला, वह नहर कोठी की छत है। यह पूरा भवन करीब दस वर्ष से खाली व जर्जर हो चुका है। बताया कि जब से नहर विभाग का पानी का टैक्स माफ हुआ है। तब से भवन खाली है। देखरेख के अभाव में नहर कोठी जर्जर भी है। यहां अक्सर नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यह पूरा भवन करीब पांच बीघा में बना है।

साढ़े चार क्विंटल विस्फोटक बरामद

सीतापुर, (संवाददाता)। दिवाली नजदीक आते ही विस्फोटक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को भी खैराबाद व कोतवाली देहात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से साढ़े चार क्विंटल विस्फोटक बरामद हुआ है। इसमें खतरनाक सुतली बम व अन्य पटाखे शामिल हैं। खैराबाद पुलिस ने रविवार देर रात ढाई लाख रुपये के पटाखों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बिसवां रोड पुरानी बाजार से मोहल्ला पनवाड़िया निवासी लल्लूराम को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक लाख रुपये कीमत के पटाखे बरामद हुए। इसके अलावा मोहल्ला रौजा दरवाजा से मोहल्ला इफ्तिकार हुसैन को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने के साथ बिक्री भी कर रहे थे। इनके पास से पकड़े गए पटाखों में खतरनाक सुतली बम भी शामिल है। आरोपी के पास से एक लाख 50 हजार रुपये कीमत के पटाखे मिले। आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर कोतवाली के ग्रीकगंज निवासी क्षितिज जायसवाल व कोतवाली देहात के भगवानपुर गांव निवासी संदीप श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच बोरियों व 13 पेटियों में करीब दो क्विंटल विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इन पटाखों को बिना लाइसेंस के भंडारित किया गया था। साथ ही अवैध ढंग से बिक्री की जा रही थी। प्रभारी निरीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों पर कार्रवाई की जा रही है।

जागे जिम्मेदार, लगाया गया ट्री गार्ड

सीतापुर, (संवाददाता)। शहर में सरायन नदी के किनारे लगाए गए पौधों के ट्री गार्ड गायब होने की खबर का जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने संज्ञान लिया। सोमवार को डीएम के निर्देश के बाद पहुंचे नगर पालिका परिषद कर्मचारियों ने एक पौधे पर ट्री गार्ड लगाकर उसे जीवनदान दिया। सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया कि कुछ स्मैकियों ने ट्री गार्ड उखाड़कर फेंक दिए थे। मौके पर मिले ट्री गार्ड को वापस स्थापित किया गया है। प्रयास है कि पौधों का संरक्षण होता रहे। सरायन नदी के पुनरुद्धार के संकल्प को पूरा करने के लिए डीएम अभिषेक आनंद ने मुहिम छेड़ी है। सरायन नदी की साफ–सफाई के बाद राज्यमंत्री, डीएम सहित अन्य अफसरों ने पौधरोपण करके सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत कराई थी। पौधरोपण के साथ पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए थे। इसके बाद नदी के किनारे से दो दर्जन से अधिक ट्री गार्ड गायब हो गए। इसके बाद पौधों को आवारा मवेशी खा गए। अमर उजाला ने 13 अक्तूबर के अंक में नदी में पड़ा ट्री गार्ड, मवेशी खा गए पौधे शीर्षक खबर प्रकाशित की थी। डीएम ने प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी को ट्री गार्ड लगवाने के निर्देश दिये। इसके बाद जिम्मेदार जागे और पौधे के साथ ट्री गार्ड को स्थापित किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सोमवार सुबह कर्मचारी आए और एक पौधे को सीधा कर ट्री गार्ड को नदी से निकालकर लगा गये। इस दौरान किसी ने यह नहीं बताया कि जिन पौधों को मवेशी खा गए हैं, उन्हें दोबारा रोपा जाएगा या नहीं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि अभी कई ट्री गार्ड और पौधे गायब हैं। इन्हें दोबारा स्थापित कराया जाए। तभी सरायन नदी का पुरुद्धार हो सकेगा।

छुट्टा पशुओं को पकड़कर आश्रय स्थल पहुंचाएं – सीडीओ

भदोही, (संवाददाता)। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड से कृषि, उद्यान, गौ आश्रय स्थल पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया। सीडीओ ने कहा कि गोवंश का भुगतान समय से सुनिश्चित करें। बीडीओ विशेष अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को कैटल कैचर से पकड़कर गौआश्रय स्थल में संरक्षित कराएं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) सोलर पंप योजना पर बल देते हुए

पंचायतों को महिला हितैषी बनाने पर दिया जोर

भदोही, (संवाददाता)। विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में सोमवार को मिशन शक्ति के तहत महिला ग्राम प्रधानों की तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 36 महिला ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। वक्ताओं ने महिला सशक्तीकरण और पंचायतों को महिला हितैषी बनाने पर जोर दिया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।